कपास का उत्पादन

219. **श्री मोर्जा इर्शादबेग** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष कपास का उत्पादन उसकी मांग से अधिक था और क्या इस वर्ष भी उसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक रहेगा ;

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान मुख्य किस्म की लम्बे रेशे तथा छोटे रेशे की कपास के बाजार मूल्य क्या थे और क्या पिछले चार वर्षों में प्रचलित मूल्यों की तुलना में वर्तमान मूल्य कम है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा किसान को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) इस वर्ष के दौरान कपास बाजार में कब से आना आरम्भ हुई है तथा कपास के समर्थन मूल्य की घोषणा कब की गयी थी तथा समर्थन मूल्य की घोषणा में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या किसानों को अपनी उपज के उचित मूल्य प्राप्त हो चुके हैं तथा इस विषय में सरकार का भावी कार्यक्रम क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान):(क)से (घ) गत रुई मौसम और वर्तमान रुई मौसम के दौरान देश में रुई अनुमानित उत्पादन तथा खपत के अनुमानित आंकड़ों का अनुमान निम्नोक्त प्रकार है : —

रुई वर्ष	(आंकड़े 170 कि० ग्रा० की प्रत्येक गांठ लाख गांठों में	
	उत्पादन	खपत
1984–85	101.50	91.15
1985–86	94.00	91.65

1981–82 से रुई की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों की कीमतों का उतार–चढ़ाव संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है (देखिये परिशिष्ट (cxxxvii , अनुपत्र संख्या 4) । चालू रुई मौसम के दौरान रुई की कीमतों में, गत मौसम की इसी अवधि में चल रही कीमतों की तुलना में, गिरावट का रुख रहा है : इसका कारण गत मौसम की बेहतर फसल और चालू मौसम के दौरान संतोषजनक फसल के आसार हैं । भारतीय रुई निगम रुई उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के लिये बाजार में पहले ही कार्य कर रहा है । सरकार ने चालू रुई मौसम के दौरान अभी तक निर्यात के लिए लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 10 लाख गांठें, बंगाल देशी की 52,000 गांठें तथा यलों पिकिन्स की 25000 गांठें रिलीज की हैं । सरकार ने एक उदारीकृत दीर्घावधि यानें निर्यात नीति की भी घोषणा की है । इन उपायों से किसानों को लाभकारी कीमतें निश्चित करने में सहायता मिलेगी ।

रुई मौसम प्रत्येक वर्ष सितम्बर से आरम्भ होता है तथापि, विभिन्न रुई उत्पादक राज्यों में रुई की आवक अलग अलग समय पर होती है । भारत सरकार द्वारा चालू मौसम के लिए कपास की न्यूनतम समर्थन कीमतें 20 नवम्बर, 1985 को घोषित की गई थीं । तथापि, इससे पहले भारतीय रुई निगम को कीमत में यदि हो सके तो समायोजना के आधार पर गत रुई मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों पर खरीद करने को कहा गया था । भारत सरकार द्वारा किसानों से रुई खरीदने के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन कीमतें लाभकारी मानी गई हैं ।

Import of coins to meet shortage

220. SHRI V. GOPALSAMY:

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA:

SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 24 given in the Rajya Sabha on the 19th November, 1985 and state:

(a) how many pieces of coins of different denomination have so far been re-